तत्काल

सं. एन-22/2/2021-पी एंड सी

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक 11 मई, 2022

विषय:- उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में अप्रैल, 2022 माह के लिए मंत्रिमंडल के लिए मासिक सारांश – के संबंध में।

****

अधोहस्ताक्षरी को इस पत्र के अनुलग्नक के रूप में, उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में अप्रैल, 2022 माह के लिए मासिक सारांश (अनुलग्नक) के अवर्गीकृत भाग को सूचनार्थ संलग्न करने का निदेश हुआ है।

संलग्नक:यथोक्त

(सुरेन्द्र सिंह)

निदेशक, भारत सरकार

फोन नं. 2338 4390

प्रति संलग्नकों सहित, ई मेल के माध्यम से अग्रेषित

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य।
2. पीआईबी/सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।
3. उपराष्ट्रपति के सचिव।
4. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
5. सचिवगण, भारत सरकार। (सूची के अनुसार)
6. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
8. निदेशक (एनआईसी) को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
9. विभाग के सहायक निदेशक (राजभाषा)

उपभोक्ता मामले विभाग

अप्रैल, 2022 माह के दौरान उपभोक्ता मामले विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप

अप्रैल, 2022 माह के दौरान उपभोक्ता मामले विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्नानुसार हैं।

1. उपभोक्ता संरक्षण :

1.1 माह के दौरान, केरल में ई-दाखिल पोर्टल शुरू किया गया, इसके साथ ही, ई-फाइलिंग पोर्टल शुरू करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कुल संख्या 31+एनसीडीआरसी हो गई है।

1.2 कॉनफोनेट योजना की समीक्षा के लिए एनआईसी और एनआईसीएसआई के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। उपभोक्ता आयोगों हेतु उनकी प्रणाली को अपनाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय की ई-कोर्ट्स समिति से संपर्क करने का निर्णय लिया गया है।

1.3 उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के लिए मौजूदा टोल फ्री नंबर 1800-11-4000 के अलावा, एक नया 4-अंकों का लघु कोड प्राप्त किया गया है। 01 मई 2022 से क्षेत्रीय भाषाओं में कॉल को पूरा करने के लिए 60 नई सीटें स्थापित की गई हैं। इसके अलावा, उपभोक्ताओं के बीच हेल्पलाइन नंबर को याद रखने और लोकप्रिय बनाने में आसानी के लिए विभाग अंतिम में 1915 संख्याओं वाली एक नई सिम प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

2. मूल्य निगरानी:

2.1 14 अप्रैल 2022 को मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सीओएस की एक बैठक हुई जिसमें विभाग ने दालों और सब्जियों (प्याज, आलू और टमाटर) के संबंध में सीओएम के निर्णयों और कीमतों के परिदृश्य पर कृत कार्रवाई की स्थिति प्रस्तुत की।

2.2 30 सितंबर 2022 तक 5.5 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) जीएम सोया मील के आयात की अनुमति संबंधी डीएएचडी के प्रस्ताव के लिए सीओएम की मंजूरी प्राप्त की गई थी।

2.3 एग्रीवॉच (कृषि उत्पादों की निगरानी) की साप्ताहिक प्रस्तुति सचिव (उ.मा.) को दी गई जिसमें पांच दालों (ग्राम, तूर, उड़द, मूंग और चना) और तीन सब्जियों (प्याज, आलू और टमाटर) की कीमतों, उत्पादन, उपज और आयात और निर्यात परिदृश्य को कवर किया गया है।

2.4 राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा यथासंसूचित आवश्यक वस्तुओं की अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्यों के अनुसार, मार्च, 2022 की तुलना में अप्रैल, 2022 माह के लिए मूल्य रुझान **अनुलग्नक-I** में दिए गए हैं।

3. मूल्य स्थिरीकरण कोष:

3.1 राज्य स्तरीय मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के प्रस्तावों और कोष के उपयोग की स्थिति की समीक्षा के लिए 22 अप्रैल 2022 को राज्य सरकारों के साथ वीडियो कान्फ्रेंस आयोजित की गई थी।

3.2 बफर स्टॉक के लिए 2.50 लाख मीट्रिक टन रबी 2022 प्याज की खरीद के लिए पीएसएफ से नेफेड को 50 करोड़ रुपये जारी किए गए।

3.3 पीएसएफ के अंतर्गत 1 लाख मीट्रिक टन आयातित मसूर की खरीद के लिए तीसरी किस्त के रूप में नेफेड को 200 करोड़ रुपये जारी किए गए।

3.4 पीएसएस से पीएसएफ को हस्तांतरित 1.20 एलएमटी चना के अंतर भुगतान के रूप में 83.05 करोड़ रुपये जारी किए गए।

3.5 प्रशासनिक व्यय की दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में एसएफएसी को 0.25 करोड़ रुपये जारी किए गए।

4. भारतीय मानक ब्यूरो:

4.1 06 अप्रैल, 2022 को आईएस/आईएसओ 56000 श्रृंखला पर नवाचार के लिए रीइनवेंटिंग आर्गनाइजेशन पर इनोमंत्रा के सहयोग से बीआईएस द्वारा एक वेबिनार का आयोजन किया गया था।

4.2 बैटरी स्वैप और इंटरऑपरेबिलिटी मानक विषय पर 13 अप्रैल 2022 को मेरी अध्यक्षता में एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में कुल 51 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस बैठक में एलईवी बैटरी स्वैप पर भारतीय मानकों के विकास के संबंध में उद्योग जगत और उद्योग संघों की चिंताओं पर चर्चा की गई।

4.3 बीआईएस ने 19 अप्रैल 2022 को उन शैक्षणिक संस्थानों जिनके साथ बीआईएस ने मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, के साथ एक आभासी परिचर्चा का आयोजन किया । महानिदेशक (बीआईएस) ने संस्थानों के अधिकारियों को मानकीकरण के क्षेत्र में कार्यों को मजबूत करने की आवश्यकता पर संबोधित किया।

4.4 घरेलू विनिर्माताओं को 353 नए लाइसेंस स्वीकृत किए गए। इसके अलावा, घरेलू निर्माताओं को 30,842 लाइसेंस स्वीकृत किए गए और विदेशी निर्माताओं को 45 लाइसेंसों का नवीनीकरण किया गया।

4.5 पटना प्रयोगशाला ने आईएस1417:2016 और आईएस 1418:2009 के अनुसार परीक्षण सुविधाएं बनाई हैं, आईएस 9873 (भाग 1): 2017 के लिए परीक्षण सुविधा का सृजन दक्षिणी क्षेत्रीय प्रयोगशाला द्वारा किया गया है, सीएल-1 ने आईएस 4151 और आईएस 9973 के खंड 4.6 के लिए परीक्षण सुविधा बनाई है और पश्चिमी क्षेत्रीय प्रयोगशाला ने आईएस 14927 (भाग 2), आईएस 302 (भाग 2/एसईसी14) और आईएस 366 के लिए नई परीक्षण सुविधा बनाई है।

4.6 हॉलमार्किंग योजना के तहत, 1130 नए ज्वैलर्स पंजीकृत किए गए हैं, और माह के दौरान 24 नए एएंडएच केंद्रों को मान्यता दी गई है।

4.7 'स्वर्ण आभूषणों और स्वर्ण कलाकृतियों की हॉलमार्किंग (संशोधन) आदेश, 2022' को केंद्र सरकार द्वारा 04 अप्रैल 2022 को अधिसूचित किया गया है, जिसके तहत अनिवार्य हॉलमार्किंग के लिए जिलों की संख्या 256 से बढ़कर 288 हो गई है। इस आदेश में आईएस 1417 अर्थात 14 कैरेट, 18 कैरेट , 20 कैरेट, 22 कैरेट, 23 कैरेट और 24 कैरेट के तहत कवर किए गए सभी ग्रेड भी शामिल होंगे। यह आदेश 1 जून, 2022 से प्रभावी होगा।

5. व्यवसाय करने की सुगमता:

कारोबार की सुगमता के लिए विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 पर कार्यशाला में मूलभूत कार्य करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। बैठक/कार्यशाला को माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है और इसे 09 मई 2022 को आयोजित किया जाएगा।

6. समय प्रसार:

एनपीएल और इसरो द्वारा परियोजना की स्थिति से अवगत कराने के लिए अप्रैल, 2022 के दौरान समय प्रसार परियोजना पर एक बैठक आयोजित की गई थी।

7. एसीसी निर्देश: सुश्री रूपा दत्ता के कार्यमुक्त होने के बाद वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार का पद 17.07.2021 से रिक्त है। इस पद के लिए संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण होने के नाते आर्थिक कार्य विभाग द्वारा इस पद को भरा जाना चाहिए। अत:, विभाग के पास कोई एसीसी निदेश लंबित नहीं है।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतें – पिछले माह की तुलना में रूझान :

राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के संबंधित नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश भर के 179 केन्द्रों से 22 आवश्यक वस्तुओं की अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्यों को संकलित किया जाता है तथा मार्च, 2022 की तुलना में अप्रैल, 2022 के महीने के लिए औसत खुदरा कीमतों का विवरण निम्नलिखित है:-

आवश्यक वस्तुओं के अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्य (₹/कि.ग्रा.)

क्रम सं.	वस्तु	अप्रैल, 2022	मार्च, 2022	अंतर (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चावल	36	36	0
2	गेहूं	29	29	0
3	आटा	32	32	0
4	चना दाल	74	75	-1
5	तूर दाल	103	103	0
6	उड़द दाल	105	105	0
7	मूंग दाल	103	102	1
8	मसूर दाल	96	97	-1
9	चीनी	41	41	0
10	दूध (प्रति लीटर)	51	51	0
11	मूँगफली का तेल	189	185	4
12	सरसों का तेल	189	192	-3
13	वनस्पति	157	152	5
14	सोया तेल	166	160	6
15	सूरजमुखी का तेल	183	176	7
16	पॉम ऑयल	150	146	4
17	गुड़	48	48	0
18	खुली चाय	284	286	-2
19	नमक का पैक	19	19	0
20	आलू	21	21	0
21	प्याज	26	32	-6
22	टमाटर	27	23	4

स्रोत: राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग